



2026:AHC:5065

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44757 सन् 2025

विजय सैनी

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: राफीक अहमद खान

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री राफीक अहमद खान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक विजय सैनी की ओर से वाद अपराध संख्या 373 वर्ष 2025, धारा 3(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 66-C सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा 4/21 खान और खनिज अधिनियम, थाना कोतवाली नगर (महोबा), जिला महोबा, में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है और वह दिनांक 28.8.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विकास राजौरिया को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41274 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उसका कोई आपराधिक इतिवृत्त नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में न्याय से भागने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत का विरोध किया, किन्तु उपरोक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

समस्त उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, समर्थनकारी साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त, किन्तु मामले की गुणावगुणता पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

तदनुसार जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **विजय सैनी** को व्यक्तिगत मुचलके तथा उसी राशि की दो विश्वसनीय जमानतों पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा

08 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)